This question paper contains 8+4 printed pages]

HPAS (Main)—2016

LAW

Paper I

Time : 3 *Hours* *Maximum Marks :* 100

Note :— Part 'A' is compulsory and answer *four* questions from Part 'B'. *All* questions carry equal marks. Give reasons for your answer supported by relevant statutory provisions and case law. Write all parts of a question at one place in continuity.

भाग 'अ' अनिवार्य है तथा भाग 'ब' से कोई **चार** प्रश्नों के उत्तर दीजिए । **सभी** प्रश्नों के अंक समान हैं । अपने उत्तरों के लिए सुसंगत कानूनी उपबन्धों तथा वाद विधि से समर्थित कारणों को दीजिए । एक प्रश्न के सभी भागों के उत्तर एक स्थान पर सतत् (लगातार) रूप में दीजिए ।

P.T.O.

Part 'A'

(भाग 'अ')

1. (*a*) "Clear proof 'custom' would outweigh the written text of law." Explain. 6

(*b*) "No person shall be deprived of his property save by authority of Law." Discuss and cited the cases. 8

(*c*) "Marxist concept of legal theory had a impact on the Western Conception of Law." Explain. 6

(क) "स्पष्ट सिद्ध 'प्रथा' विधि के लिखित पाठ्य को निरहीत कर देती है।" व्याख्या कीजिए।

(ख) "कोई व्यक्ति विधि के अधिकार के सिवाय अपनी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा।" विवेचना कीजिए और वादों का उदाहरण दीजिए।

(ग) "विधिक सिद्धान्त की मार्क्सवादी विचारधारा का विधि की पाश्चात्य संकल्पनाओं पर प्रभाव था।" व्याख्या कीजिए।

Part 'B'

(भाग 'ब')

2. (*a*) "Judges of the Supreme Court must not forget law has a social purpose and an engineering process without appreciating, which justice to law cannot be done. Law is meant to serve the living and does not beat its wings in the Jural void." Comment. 10

(*b*) "Hanging by rope amounts to murder with cruelty. Such procedure for ending life should be adopted which would be least painful." Give reasons

in its support and against it mentioning Supreme Court decisions and relevant Articles of the Constitution of India on it. 10

(क) "उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपतियों को यह नहीं भूलना चाहिये कि विधि एक सामाजिक प्रयोजन और अभियांत्रिक प्रक्रियां है जिसको समझे बिना विधि के प्रति न्याय नहीं हो सकता है। विधि जीवित की सेवा के लिए है। वह अपने पंख न्यायायिक शून्य में नहीं फड़फड़ाता है।" टिप्पणी कीजिए।

(ख) "रस्सी से लटका कर फाँसी देना निर्दयतापूर्ण हत्या है। इसको समाप्त करके ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए जो कम से कम कष्टदायी हो।" पक्ष–विपक्ष के तर्कों को दीजिए। उच्चतम न्यायालय के निर्णय और भारतीय संविधान के प्रावधानों के मत व्यक्त करते हुए अपना उत्तर दीजिए।

3. (*a*) Analyse the expansion of Article 21 of the Indian Constitution by the Supreme Court since 2007. 10

(*b*) "Sanctions is an essential element of Law. Law without sanction is only positive morality."

Examine the above statement in view of the Positive School of Jurisprudence. 10

(क) उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के विस्तार की 2007 से विवेचना कीजिए।

(ख) "शास्ति विधि का एक आवश्यक तत्व है। बिना शास्ति के विधि केवल सकारात्मक नैतिकता है।"

इस कथन का विधिशास्त्र की विध्यात्मक विचारधारा के प्रकाश में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

4. (*a*) "Article 13 confers a power as well as imposes an obligation on the courts to check the violation of fundamental rights." Explain. 10

(*b*) "Law is all about balancing the competing interests in the society."

In view of the above statement, discuss Roscoe Pound's theory of social engineering along with its criticism. 10

(क) "मूल अधिकारों के उल्लंघन को रोकने हेतु अनुच्छेद 13, न्यायालयों को शक्ति प्रदान करने के साथ-साथ एक बाध्यता भी आरोपित करती है।" व्याख्या कीजिए।

(ख) "विधि समाज में प्रतिस्पर्धी हितों का संतुलन है।" ऊपर के कथन की दृष्टि में रास्को. पाउण्ड की सामाजिक अभियंता सिद्धान्त की आलोचना सहित विवेचना कीजिए।

5. (a) Discuss the procedure for the recovery of Land Revenue under the H.P. Land Revenue Act, 1953. What property can be attached for this purpose ? 10

(*b*) (*i*) Discuss the Marxist theory of Law and Economics. 5

(*ii*) Marxists believe that "Law arises from class conflicts caused by property." Explain. 5

(क) हिमाचल प्रदेश भूमि अधिनिमय, 1953 के भू-राजस्व वसूली की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। इस हेतु कौनसी सम्पत्ति कुर्क की जा सकती है ?

(ख) (*i*) विधि एवं अर्थशास्त्र के मार्क्सवादी सिद्धान्त की विवेचना कीजिए।

(*ii*) मार्क्सवादियों का विचार है कि "सम्पत्ति से उत्पन्न वर्ग संघर्ष से विधि का उदय होता है"।

6. (*a*) (*i*) Discuss the composition and jurisdiction of Revenue Courts under the H.P. Land Revenue Act, 1954. 5

(*ii*) Discuss the power and functions of Financial Commissioner under the H.P. Land Revenue Act, 1954. 5

(*b*) Analyse the Marxist and Friedrich Engels Contribution regarding the Social and Political Movement in 19th century. 10

(क) (*i*) हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिनियम, 1954 में राजस्व न्यायालयों के संगठन और क्षेत्र अधिकारों की विवेचना कीजिए।

(*ii*) हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिनियम, 1954 के आधीन फाइनेंस कमिश्नर के कार्यों और अधिकारों की व्याख्या कीजिए।

(ख) 19वीं सदी के सामाजिक व राजनीतिक आन्दोलन के सम्बन्ध में मार्क्स व फ्रेडरिक एन्जिल्स के योगदान का विश्लेषण कीजिए।

7. (*a*) Explain the provisions of H.P. Land Revenue Act, 1954 relating to Mutation on the death of a tenure holder. What is the procedure of Inheritance or transfer in disputed ? 10

(*b*) Explain the functions and the jurisdiction of the "Kanungos' and Village officers" under the H.P. Land Revenue Act, 1954. Cited cases. 10

(क) हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिनियम, 1954 के उन उपबन्धों की व्याख्या कीजिए जो भूधृतिधारी की मृत्यु पर

दाखिल खारिज से सम्बन्ध रखते हैं। जब उत्तराधिकार या हस्तांतरण विवादस्पद होता है तथा क्रिया प्रक्रिया होती है।

(ख) हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत "कानूनगो तथा गाँव अधिकारी" के कार्यों तथा क्षेत्राधिकारों की व्याख्या कीजिए। वादों का उदाहरण दीजिए।

8. (*a*) How far the judgements of the Supreme Court and the Privy Council are binding on Indian Courts ? And how far the judgements of the Supreme Court and the High Courts are binding on them ? 10

(*b*) What reforms do you suggest in the system of Judiciary and in the system of appointment of High Court and the Supreme Court Judges in the light of the recent Supreme Court Judgement. 10

P.T.O.

(क) उच्चतम न्यायालय एवं प्रिवी काउन्सिल के निर्णय किस प्रकार से भारतीय न्यायालयों पर लागू होते हैं और उच्चतम और उच्च न्यायालयों के निर्णय उन्हीं न्यायालयों पर किस प्रकार से बाध्यकारी होते हैं ?

(ख) भारतीय न्यायिक प्रणाली में आप किन सुधारों की आवश्यकता समझते हैं ? उच्च न्यायालयों के न्यायाधिपतियों की नियुक्ति में आप किन सुधारों का सुझाव अभी उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में देते हैं ?